सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 31 OCTOBER TO 06 NOVEMBER 2025 • VOLUME 15 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"खुश रहना एक कला है, जिसे हर कोई सीख सकता है।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	31°	17°
शनिवार	28°	16°
रविवार	36°	16°
सोमवार	36°	16°
मंगलवार	34°	14°
बुधवार	33°	14°
वीरवार	33°	15°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत

मुंबई पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

मुंबई. मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को तनावपूर्ण बंधक स्थिति का नाटकीय अंत हो गया जब कथित तौर पर आरोपी रोहित आर्या की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आर्या जिसने पहले आरए स्टूडियो के अंदर कई बच्चों को बंधक बनाया था, पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया और उसे जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। मुंबई के पवई इलाके में कई बच्चों के अपहरण के आरोपी रोहित आर्या की बंधकों को छुड़ाने के लिए पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, जब पुलिस बाथरूम के रास्ते आरए स्टूडियो में दाखिल हुई तो आरोपी एयर गन से लैस था और उसके पास कुछ रासायनिक पदार्थ थे।

अधिकारियों ने उसे बार-बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, पुलिस को उसके आक्रामक व्यवहार के जवाब में गोली चलानी पड़ी। इस मुठभेड़ में आर्या को गोली लग गई। उसे तुरंत इलाज के लिए जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया जहाँ बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी बच्चों को बचाने की कोशिश के दौरान हुई, जिन्हें परिसर से सुरक्षित निकाल लिया गया। टकराव की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जाँच चल रही है।

घटना तब शुरू हुई जब पुणे निवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त रोहित आर्या ने कथित तौर पर एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के बहाने आरए स्टूडियो में 17 बच्चों, एक वरिष्ठ नागरिक और एक अन्य नागरिक को बुलाया। अंदर घुसते ही उसने दरवाज़े बंद कर दिए और समूह को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। पुलिस को दोपहर करीब 1:45 बजे एक आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और विशेष इकाइयों ने इमारत को घेर लिया। पहले तो बंधकों को शांतिपूर्वक रिहा कराने के लिए बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जब बातचीत विफल रही तो पुलिस बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में घुस गई।

एक सावधानीपूर्वक समन्वित अभियान में पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने 17 बच्चों सहित सभी 19 व्यक्तियों को बचा लिया। बंधकों को स्टूडियो के भूतल पर बंधक पाया गया। पुलिस उपायुक्त दत्ता किशन नलावड़े के अनुसार, बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के पास पहुँच गए हैं। अधिकारी ने पुष्टि की कि जाँच का केंद्र आर्या के इरादों और मानसिक स्थिति का पता लगाना था।

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति कांत 23 नवंबर को सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। वह देश के 53वें सीजेआई होंगे और 9 फरवरी, 2027 तक 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पोस्ट में कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 10 फ़रवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वे उन पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।

आरजेडी का मतलब 'कट्टा, क्रूरता, कुशासन का जंगलराज' : पीएम मोदी

पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला बोला और उस पर बिहार को 'जंगल राज' के युग में धकेलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि राजद का शासन 'कट्टा (बंदूक), क्रूर (क्रूरता), कटुता (कड़वाहट), कुशासन (कुशासन) और भ्रष्टाचार' से भरा रहा है।

उन्होंने लोगों से ऐसी राजनीति को नकारने और आगामी विधानसभा चुनावों में विकास और स्थिरता का समर्थन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर भी हमला बोलते हुए उन पर राजनीतिक लाभ के लिए छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छठी मैया के बारे में विपक्ष की कथित टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा, "क्या कोई चुनाव में वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार और देश की जनता ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगी?" उनकी टिप्पणी पर दर्शकों ने ज़ोरदार तालियाँ बजाईं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।"

कांग्रेसी बिहारियों के अपमान पर बजाते हैं ताली : चिराग

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कांग्रेस पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ 'दुर्व्यवहार' होता है, तो उसके नेता ताली बजाते हैं। लोजपा (रामविलास) प्रमुख 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने के लिए छपरा में थे। पासवान ने कहा कि मैंने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि दूसरे राज्यों में बिहारियों का अपमान किया जाता है। जिस तरह से 'बिहारी' शब्द को भी गाली में बदल दिया गया था, और दुख की बात है कि सभी सत्तारूढ़ दल इसी स्थिति में थी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि कैसे पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गांधी परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति में, बिहारियों को पंजाब में प्रवेश न करने की धमकी दे रहे थे, जबकि कांग्रेस के सदस्य तालियाँ बजा रहे थे।

सीबीएसई ने जारी की कक्षा दसवीं और बारहवीं की फाइनल डेटशीट

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा की एग्जाम डेट शीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर फाइनल डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होंगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी (एनईपी-2020) के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा केवल एक शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

जालंधर में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जालंधर में गुरुवार को दिनदहाड़े एक ज्वेलर की दुकान को लूट लिया गया। हथियारों से लैस तीन नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश भीतर घुसे और आते ही ज्वेलर पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बदमाशों ने एकाएक दुकान के सभी आभूषणों को अपने बैग में डालना शुरू कर दिया। हाथ में लिए तलवार से बदमाशों ने काउंटर के शीशों को तोड़ा और उसमें रखे आभूषण निकाल लिए। कुछ ही मिनट में कैश और ज्वेलरी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। ये वारदात भार्गव कैंप इलाके में विजय ज्वेलर शॉप में हुई। वारदात के वक्त ज्वेलर का बेटा दीपक दुकान में बैठा हुआ था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि लुटेरे 2 लाख से अधिक नकदी और गहने लेकर फरार हो गए।

अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी : एडीसीपी-2

जालंधर के भार्गव कैंप में एक ज्वेलरी की दुकान में हुई डकैती की घटना के बारे में जालंधर के एडीसीपी-2 हरिंदर सिंह गिल ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना प्रातःकाल हुई और सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच गईं। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच जारी है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शायद हमें किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ना पड़े : कैप्टन अमरिंदर सिंह

मोगा. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को मोगा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर बाद बाहर आया हूं। मेरी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी। कैप्टन ने कहा कि 2027 में पंजाब विधानसभा का इलेक्शन तो दूर है। इससे पहले ही माहौल गर्म हो जाएगा। हम खुलकर भाजपा की मदद करेंगे। लोगों का भाजपा के प्रति नजरिया बदला है। इसका हमें आने वाले समय में फायदा मिलेगा। राहुल गांधी के पीएम मोदी के डांस करने को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि राहुल गांधी को समझ ही नहीं है। क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता। आपने देखा भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को डांस करते। डांस तो ट्रंप करता है।

2027 विधानसभा इलेक्शन में दूसरी पार्टियों के साथ समझौते के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने पंजाब के लिए काम किया है। लोगों ने पार्टी के प्रति पॉजिटिविटी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद हमें किसी दूसरी पार्टी के साथ समझौते की जरूरत ही न पड़े। कैप्टन ने कहा कि तरनतारन में हो रहे उपचुनाव को लेकर अभी मैं वहां नहीं जा पाया हूं। आने वाले दिनों में वहां जाने की योजना है। शायद मैं जल्द ही वहां पर जाऊं।

सरहद पार से अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश; नौ पिस्तौलों सहित तीन गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने तीन गुर्गों को गिरफ्तार कर सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उनके कब्जे से मैगजीन सहित नौ आधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान दविंदर सिंह, निवासी गांव भंगवां, अमृतसर ग्रामीण, परमजीत सिंह उर्फ़ पम्मा और हरमीत सिंह उर्फ़ मीटू, दोनों निवासी भिंडी औलख, अमृतसर ग्रामीण के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किये गये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए हथियार पंजाब में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ़ बिल्ला मंगा के करीबी सहयोगी शेरप्रीत सिंह उर्फ़ गुलाबा को सप्लाई किए जाने थे। डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर को विदेश में स्थित नामी गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ़ बिल्ला मंगा के बारे में विशेष जानकारी मिली थी, जो अपने साथियों परमजीत सिंह उर्फ़ पम्मा और हरमीत सिंह उर्फ़ मीटू के ज़रिए राज्य में गैंग चला रहा था। इस सूचना से आगे पता चला कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप प्राप्त की है, जिसे सरहद पार से ड्रोन की मदद से गांव भिंडी औलख ,अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में गिराया गया था, और वे इसे आगे शेरप्रीत के साथी दविंदर सिंह तक पहुँचाने वाले थे।

राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का शुभारंभ

शिवराज सिंह की पहल पर 24 राज्यों व 140 जिलों के सैकड़ों किसान, एफपीओ, सीबीबीओ और एजेंसियों की समागम में सहभागिता

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में "राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025" का शुभारंभ किया। इस आयोजन में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, एफपीओ, कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) और क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) शामिल हुए हैं। मंत्री चौहान ने किसानों, एफपीओ सदस्यों और सहभागी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की और एफपीओ के माध्यम से किसानों को उत्पादक के साथ ही व्यापारी और उद्यमी बनाने का भी आह्वान किया, ताकि पूरा लाभ सीधे किसानों को मिल सकें। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने देश के किसान हितों से कोई समझौता नहीं करने के दृढ़ संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की ओर से आभार माना। साथ ही कहा कि आजीविका के साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेती बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के फायदे के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हमारा फोकस है। अकेले अनाज से काम नहीं चलेगा, साथ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य संबद्ध कार्य भी करना होंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मंत्री के नाते मेरी चिंता है कि किसानों को उनकी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल की अच्छी कीमत मिलें, किसान दिन रात अथक परिश्रम करके अपनी फसल उगाते है, कई बार उन्हें समुचित कीमत नहीं मिलती, वहीं उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर ये खरीदना पड़ता है, इस अंतर को कम करना होगा। शिवराज सिंह ने कहा कि हम सीड एक्ट भी जल्दी लाने वाले है, जिसमें प्रावधान होगा कि किसानों को अच्छी क्वॉलिटी के बीज मिले। शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि नकली और घटिया बीज और पेस्टीसाइड के मामले में सरकार सख्त है, हम कड़ा कानून लाएंगे और हमारे किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

पटियाला में मान और केजरीवाल द्वारा 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ

केजरीवाल ने कहा- माता रानी की कृपा से एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट

• **जालंधर ब्रीज.** पटियाला

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से आज ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर के नवीनीकरण के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह प्रदेश सरकार का विशेष दायित्व बनता है कि वह अधिक जन महत्व वाले ऐसे प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दे। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली प्रदेश सरकारों ने कभी भी जन महत्व वाले इन कार्यों को करने की इच्छा नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि माता रानी ने आप के नेतृत्व वाली सरकार को यह मौका दिया है। उन्होंने कहा कि यह काम एक साल के अंदर-अंदर पूरा कर लिया जाएगा। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि श्री काली माता मंदिर उत्तरी भारत के सबसे सम्मानित और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर पंजाब की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और शाही संरक्षण का प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर परिसर में काली माता को समर्पित मुख्य मंदिर के साथ शक्ति के ब्रह्म स्वरूप राज राजेश्वरी जी का प्राचीन मंदिर भी है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि श्रद्धा के ये दोनों स्थल मंदिर परिसर को आध्यात्मिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण और वास्तुकला की दृष्टि से अधिक अनोखा बनाते हैं, जहां सदियों पुरानी परंपराओं का आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बेहद सुंदर मेल देखने को मिलता है।

150 साल पहले बना था दिल्ली का एक ऐसा ऐतिहासिक पुल जिसके नीचे से निकलती हैं गाड़ियां तो ऊपर चलती है ट्रेन

Travelling

दिल्ली में आपने लोहे का ब्रिज बहुत बार देखा होगा जिसे यमुना ब्रिज भी कहते हैं, जिसे बने हुए 150 साल से अधिक हो गए हैं, जानिए इस ब्रिज के बारे में जिसके ऊपर ट्रेन चलती है तो नीचे चलती हैं गाड़ियां।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

देश की राजधानी दिल्ली जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है, इसी दिल्ली में एक ऐसा पुल भी है, जिसे देख लोग चौक जाते हैं कि ये पुल 3500 टन लोहे से बनाया गया है, इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, जबकि नीचे गाड़ियां चलती हैं, ये नजारा केवल देश की राजधानी में ही देखने को मिलता है।

यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल 150 साल पुराना है और अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। इस पुल के नीचे यमुना नदी बहती है, दिल्ली में जब-जब बाढ़ आई तब-तब पुल चट्टान की तरह खड़ा रहा था, लेकिन इस पुल पर एक प्रतिशत भी खरोंच नहीं आती।

बता दें, बाढ़ के समय ही इसे यातायात के लिए के लिए बंद किया जाता था। चलिए जानते हैं इस पुल के बारे में।

साल 1863 में हुआ था पुल का निर्माण-साल 1863 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ और 1866 में ये पूरा हो गया, इस पुल को लोहे के पुल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम यमुना पुल है।

इतनी कीमत में बना था ब्रिज

पुराना यमुना ब्रिज, जिसे रेलवे की भाषा में ब्रिज नंबर 249 कहते हैं, दिल्ली गाजियाबाद रेलखंड पर मौजूद है, इसे शुरुआत में करीबन 16 लाख 16 हजार 335 पाउंड की कीमत से एकल लाइन के रूप में बनाया था, हालांकि बाद में 1913 में इसे दोहरी लाइन में बदल दिया गया, साथ ही 1930 में पुल के नीचे बने सड़क मार्ग को चौड़ा किया गया जिससे सड़क यातायात आसानी से गुजर जाए।

मजबूत पुल की जरूरत थी

दिल्ली का लोहे वाला पुल अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था और इसके निर्माण का मुख्य कारण रेलवे कनेक्शन था, उस दौरान दिल्ली से हावड़ा तक रेल मार्ग तैयार किया जा रहा था और यमुना नदी को पार करने के लिए उस दौरान एक मजबूत पुल की जरूरत थी।

सिक्का फेंकते हैं लोग

इस पुल की खास बात ये है इस 150 साल पुराने पुल ने भांप से चलने वाली ट्रेन का युग, डीजल युग और बिजली से चलने वाली ट्रेन के समय को देखा है और इस रूट में सफर करने वाले लोगों के दिलों में इसको लेकर कई यादें और भावनाएं जुड़ी हैं। आज भी लोग इस पुल से गुजरते समय नदी और गुड़ लक के लिए सिक्का फेंकते हैं।

नानी पुल से भी जानते हैं

इस पुल को नानी पुल के नाम से भी जानते हैं, इसकी वजह से जब ये पुल पुरानी दिल्ली और शाहदरा को जोड़ने के लिए बनाया गया था, तो उस समय लोग अपनी नानी या दादी के घर आने-जाने के लिए अक्सर इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। खासकर शाहदरा और पुराने दिल्ली के बीच रिश्तेदारी वाले परिवाओं में ये पुल बेहद मशहूर था। समय के साथ लोगों की जुबान पर इसका नाम 'नानी का पुल' या 'नानी ब्रिज' पड़ गया।

अभी तक पूरा नहीं बना है ये पुल

रिपोर्ट के अनुसार पुराने लोहे के पुल को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था और अब इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। इसके जैसा ही एक नए ब्रिज को बनाने की योजना को 1997-98 में मंजूरी दी गई थी और उसका काम 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये है ये पुल अब तक पूरा नहीं बन पाया है।

LIFESTYLE

पेट के बल सोने वाले हो जाएं सावधान, गर्दन पीठ ही नहीं चेहरे की खूबसूरती के लिए भी बड़ा खतरा

पेट के बल लेटने से रीढ़ को अस्वाभाविक स्थिति में झुकना पड़ता है। इस दबाव को सहने के लिए पीठ पीछे की ओर मुड़ जाती है, जिससे रीढ़ की प्राकृतिक वक्रता (कर्व) सपाट हो जाती है और...

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

पेट के बल सोना शुरुआत में भले ही आरामदायक लगे, लेकिन यह मुद्रा लंबे समय में आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बहुत से लोग जल्दी नींद आने या खर्राटे कम करने के लिए इस स्थिति में सोना पसंद करते हैं, लेकिन शरीर पर—विशेष रूप से रीढ़ और गर्दन पर—पड़ने वाला दबाव धीरे-धीरे पुरानी तकलीफों और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

पेट के बल सोना शुरुआत में भले ही आरामदायक लगे, लेकिन यह मुद्रा लंबे समय में आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बहुत से लोग जल्दी नींद आने या खर्राटे कम करने के लिए इस स्थिति में सोना पसंद करते हैं, लेकिन शरीर पर—विशेष रूप से रीढ़ और गर्दन पर—पड़ने वाला दबाव धीरे-धीरे पुरानी तकलीफों और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

शिशु मृत्यु सिंड्रोम (SIDS)

शिशुओं के लिए पेट के बल सोना विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (SIDS) के जोखिम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसी कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शिशुओं को कभी भी पेट के बल सुलाना नहीं चाहिए।

डॉक्टर की सलाह

फोर्टिस अस्पताल (फरीदाबाद) के निदेशक एवं पल्मोनोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. रवि शेखर झा कहते हैं कि पेट के बल सोना कुछ लोगों को भले ही आरामदायक या आदतन लग सकता है, लेकिन इसके जोखिम थोड़े से आराम से कहीं अधिक गंभीर हैं। रीढ़ की हड्डी के गलत संरेखण, गर्दन के दर्द, सांस लेने में कठिनाई और सौंदर्य संबंधी दुष्प्रभाव—ये सभी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बेहतर रीढ़ संरेखण, दबाव बिंदुओं में कमी और अधिक आरामदायक नींद के लिए पीठ या करवट लेकर सोना ही सबसे सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद विकल्प है।

बचे हुए चावल से बनाएं स्वादिष्ट और चटपटा फ्राइड राइस

फ्राइड राइस एक एशियाई भोजन है जिसे बहुत ही आसान तरीके से तवा या फिर पैन में स्टिर-फ्राई करके तैयार किया जाता है। कम मेहनत से तैयार इस रेसिपी को तैयार करने में मात्र 10 मिनट का समय ही लगता है। इस रेसिपी को आप अपने मनपसंदीदा डिश के साथ खा सकते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

घर आने वाले कई मेहमान, ऐसे भी होते हैं, जो मीठा खाने से परहेज करते हैं या फिर मीठा खाकर ऊब चुके होते हैं। ऐसे मेहमानों के लिए आप एक हेल्दी स्नैक्स रेसिपी पनीर फिंगर्स बनाकर ट्राई कर सकती हैं। यह चटपटी रेसिपी ना सिर्फ खाने में टेस्टी बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है।

चाइनीज़ फ्राइड राइस रेसिपी

- तैयारी का समय : 15 मिनट
- पकाने का समय : 15 मिनट
- कुल समय : 30 मिनट
- 2-3 लोगों के लिए

सामग्री

- बासमती या लंबे दाने वाला चावल (उबला हुआ) 2 कप
- गाजर (बारीक कटी) ½ कप
- शिमला मिर्च (बारीक कटी) ½ कप
- पत्तागोभी (कटी हुई) ½ कप हरी मटर ¼ कप
- प्याज (बारीक कटा) 1
- हरा प्याज (कटा हुआ) 2 टेबलस्पून
- सोया सॉस 1 टेबलस्पून
- विनेगर 1 टेबलस्पून
- हरी मिर्च सॉस 1 टीस्पून
- टोमैटो सॉस (वैकल्पिक) 1 टीस्पून
- नमक स्वादानुसार
- काली मिर्च पाउडर ¼ टीस्पून
- तेल (रिफाइंड या ऑलिव) 2 टेबलस्पून

विधि

- चावल तैयार करें : बासमती चावल को उबाल लें (ऐसे कि दाने अलग-अलग रहें)। ठंडा होने के बाद एक तरफ रख दें।
- सब्जियाँ भूनें: एक कड़ाही या वॉक में तेल गर्म करें। इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
- फिर गाजर, मटर, शिमला मिर्च और पत्तागोभी डालें। तेज़ आंच पर 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएँ।
- सॉस मिलाएँ : अब इसमें सोया सॉस, विनेगर, हरी मिर्च सॉस और टोमैटो सॉस डालें। सबको अच्छे से मिलाएँ।
- चावल डालें : अब उबले हुए चावल डालें। नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें।
- ध्यान रखें – चावल को ज़्यादा न चलाएँ ताकि दाने टूटें नहीं।
- गार्निश करें : गैस बंद करें और ऊपर से हरा प्याज डालकर मिक्स करें।
- **सर्व करें :** गरमागरम फ्राइड राइस को मंन्चूरियन या चिली पनीर के साथ परोसें।

दिन भर उछल-कूद करता बच्चा? जानें क्या ये सिर्फ शरारत है या कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का है लक्षण

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बच्चे हैं तो मस्ती और शरारत तो करेंगे ही। यह आमतौर पर बिल्कुल सामान्य माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार उनकी ये मस्ती या शरारत वाकई सिर्फ बदमाशी है या कहीं इसके पीछे कोई गंभीर हेल्थ इश्यू छुपा तो नहीं है? क्योंकि कुछ मामलों में यह सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। पीडियाट्रिशियन डॉ. ने इस बारे में हाल ही में इंस्टाग्राम वीडियो में जानकारी दी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में डॉक्टर कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि बच्चा सिर्फ शरारती है या फिर वह ADHD (एटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) का शिकार है। इसके लिए कुछ संकेतों पर ध्यान दिया जा सकता है। बच्चा हमेशा भागता-दौड़ता रहता है और एक जगह टिककर नहीं बैठ पाता।

बीच में ही छोड़ देता है काम

एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि अगर बच्चा बीच में ही हर काम छोड़ देता है, उदाहरण के लिए, अगर कलरिंग कर रहा हो, तो उसे बीच में छोड़कर किसी दूसरे खिलौने के साथ खेलने लगता है।

खिलौने से बहुत जल्दी बोर हो जाता है

डॉक्टर कहते हैं कि अगर, बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है और खिलौना या कहानी थोड़ी देर में ही छोड़ देता है। वह बहुत ज्यादा बोलता है, हर बात को टोकता है और बिना सुने ही अपना जवाब दे देता है। अपनी बारी का इंतजार नहीं करता और जब पेरेंट्स बुलाते हैं तो सुनता ही नहीं, बस अपनी दुनिया में खोया रहता है, तो संभव है कि उसे एडीएचडी जैसी बीमारी से ग्रसतिहो। इसीलिए इस तरह के कसिी लक्षण दिखने पर पेरेंट्स फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

अपने बालों के हिसाब से कैसे चुनें हेयर ब्रश? एक्सपर्ट ने दिया जवाब

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

आपने आज सुबह बाल बनाने के लिए कौन से कंघे या ब्रश का इस्तेमाल किया? अगर आपको नहीं मालूम है, तो जान लें कि कंघा या ब्रश का चुनाव आपके बालों की सेहत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बालों की देखभाल के लिए शैंपू, ऑयलिंग के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी है।

घुंघराले बालों के लिए :-

अगर आपके बाल घुंघराले हैं, तो हेयरब्रश चुनते वक्त सावधान रहें। दर्शन की माने तो "नहाने के तुरंत बाद, गीले बालों में चौड़े दांतों वाली कंघी की मदद से सिरे से शुरू करके बीच की लंबाई तक कंघी करें। अगर बाल अधिक उलझते हैं, तो आपको डिटैंगलिंग ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग से पहले यदि बाल उलझ गए हैं, तो उन्हें दोबारा गीला करें और वापस से सुलझाने का प्रयास करें।

सीधे बालों के लिए :-

सीधे बाल वालों को ज्यादातर पैडल ब्रश (paddle brush) इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बाल कमजोर हैं, और आसानी से टूटते हैं, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। टूटते बालों का कारण समझने के लिए किसी त्वचा विशेषज्ञ से जांच करवाएं। हालांकि, रोजाना बाल झाड़ने के लिए पैडल ब्रश का इस्तेमाल करें।

क्या कोई ऐसा हेयर ब्रश है, जो सभी प्रकार के बालों पर काम करता हो?

इसपर दर्शन कहते हैं "पैडल ब्रश आमतौर पर सभी प्रकार के बालों के लिए फायदेमंद होता है। परंतु सूखे उलझे बालों को सुलझाने के लिए इसे इस्तेमाल न करें। इसलिए, उलझे बालों को तब सुलझाएं जब इनमें हल्की नमी हो। अगर बाल अक्सर उलझे रहते हैं, तो लीव-इन-कंडीशनर का इस्तेमाल करें, इससे बालों को सुलझाना आसान हो जाता है।"

घुंघराले बालों के बारे में बात करें तो, इन्हें ब्रश करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नहाने के बाद जब बाल हल्के गिले हों, तब इन्हें सिरों से ब्रश करें और पहले नीचे की गांठों को धीरे से हटाएं।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

पेट में भारीपन-खाने के बाद तुरंत नींद, 6 लक्षण चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कमजोर हो गया है डाइजेस्टिव फायर

Health

पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह ठीक से काम नहीं करता तो आपके शरीर को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिसका असर...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

पाचन क्रिया का मजबूत रहना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है। खराब पाचन के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। अगर आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपका शरीर कमजोर हो सकता है। आयुर्वेद में पेट की अग्नि यानी पाचन अग्नि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दअरसल पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है।

जब यह ठीक से काम नहीं करती तो खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अगर पाचन कमजोर होगा तो इसका असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ सकता है।

पेट में भारीपन महसूस होना : अगर हल्का भोजन खाने के बाद भी आपको पेट में भारीपन महसूस होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अक्सर ब्लोटिंग की समस्या पाचन में गड़बड़ी की ओर इशारा करती है।

बार बार गैस की समस्या : पेट में गैस बनना एक आम समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे गलत खान पान। लेकिन कम और सीमित मात्रा में भोजन करने के बाद भी आपको बार बार गैस बनने की समस्या हो रही है तो आपको बॉडी हल्के भोजन को भी ब्रेकडाउन नहीं कर पा रही है।

खाते ही तुरंत नींद आना : ज्यादातर लोगों की खाने के बाद आराम करने की आदत होती है। लेकिन खाते ही आपको तुरंत बिस्तर पर लेटने का करें तो यह नॉर्मल नहीं है। यह कमजोर अग्नि का लक्षण है। दअरसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन पचाने के लिए आपकी बॉडी को अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है।

जीभ के रंग में बदलाव : अगर आपका शरीर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आपके जीभ के रंग में भी बदलाव नजर आ सकता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिस इकट्ठा हो जाते हैं तो जीभ पर सफेद रंग की परत का जम जाती है।

पेट भरा महसूस होना : कमजोर डाइजेस्टिव फायर की वजह से भूख कम लगती है या पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा एसिडिटी, बार बार फार्ट आना या फिर डकारे आना भी पाचन अग्नि के असंतुलित होने के लक्षण होते हैं।

लगातार कब्ज की समस्या : पेट का ठीक से साफ ना होना और लगातार कब्ज की दिक्कत भी कमजोर डाइजेस्टिव फायर का लक्षण होता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह गंभीर समस्या का रूप ले सकता है।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

एक अनूठी पार्टी : भाजपा ने भारतीय राजनीति में नेतृत्व के पहलू को कैसे पुनर्परिभाषित किया

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

आजाद भारत के इतिहास में राजनीति ज्यादातर समय हक की एक ऐसी भावना से प्रभावित रही, जिसने विरासत और वैधता के बीच घालमेल किया। एक परिवार और एक पार्टी को यह लगने लगा कि वे शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। गुजरते वक्त के साथ, इस मानसिकता ने संस्थाओं को खोखला कर दिया और पीढ़ियों को राजनीतिक विशेषाधिकार को जन्मसिद्ध अधिकार मानने के लिए प्रेरित किया। इस धारणा को अब योग्यता, जवाबदेही और प्रदर्शन पर आधारित नई राजनीतिक नैतिकता द्वारा चुनौती दी जा रही है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "वन नेशन, ए फ्यू फैमिलीज" शीर्षक लेख में भारत में वंशवादी राजनीति के जारी रहने को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। यह लेख जिस मुद्दे को उजागर करता है वह वास्तविक तो है, लेकिन उसकी व्याख्या अधूरी है। वंशवाद भाजपा समेत सभी दलों में मौजूद है। फिर भी, भाजपा की एक खासियत यह है कि वहां पारिवारिक पृष्ठभूमि अपने-आप नेतृत्व में तब्दील नहीं होती। यह एक ऐसी पार्टी है जहां अवसर अर्जित करना जरूरी होता है और जहां किसी व्यक्ति का उत्थान उसके काम, प्रतिबद्धता एवं जनता के विश्वास पर निर्भर करता है, न कि वंश पर। भाजपा में, एक पारिवारिक पहचान एक दरवाजा तो खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे को हमेशा के लिए खुला नहीं रख सकता।

यह एक मौलिक अंतर है। राजनीतिक रिश्तेदारी अपने आप में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वंशानुगत नियंत्रण एक समस्या है। जब नेतृत्व एक ही परिवार की मिल्कियत बन जाए, जब आंतरिक बहस की जगह रक्त संबंधों के प्रति निष्ठा ले ले, तो लोकतंत्र मुरझा जाता है। राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का यह अंतर काफी गहरा है। वर्ष 2000 से, भारतीय जनता पार्टी के आठ राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं- बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जे.पी. नड्डा। ये सभी अलग-अलग क्षेत्रों एवं पृष्ठभूमि से आए हैं और इनमें से प्रत्येक संगठनात्मक कार्य के अनुशासन के रास्ते आगे बढ़े हैं। इसी अवधि के दौरान, कंाग्रेस के मात्र तीन अध्यक्ष ही हुए हैं, जिनमें से दो गांधी परिवार से हैं। सोनिया गांधी उन्नीस वर्षों तक इस पद पर रहीं और आज भी पार्टी में इस परिवार का निर्णय ही अंतिम होता है।

इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण, इन अंतरों को कम करके मौलिक रूप से भिन्न राजनीतिक हकीकतों को एक जैसा बना देता है। आकस्मिक रिश्तेदारी और संस्थागत कब्जे के बीच अंतर किए बिना ही, यह विश्लेषण राजनीति में रिश्तेदारों वाले विधायकों की संख्या की गिनती करता है। भाजपा के 2,078 विधायकों में से 84 राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जो लगभग चार प्रतिशत है। कांग्रेस के 857 विधायक हैं, जिनमें से 73 वंशवादी हैं, जो लगभग नौ प्रतिशत है। आनुपातिक रूप से मापने पर, कंाग्रेस का वंशवादी घनत्व दोगुना है। फिर भी, इस लेख में संख्याओं की गिनती का हवाला देकर एक झूठी समरूपता गढ़ी गई है।

कांग्रेस से परे भी, सत्ता का एक परिवार विशेष के हाथों में केन्द्रित होना ही कई क्षेत्रीय दलों की पहचान है। समाजवादी पार्टी की बागडोर मुलायम सिंह यादव से निकलकर अखिलेश यादव के पास चली गई। राष्ट्रीय जनता दल यादव परिवार के ही अधीन है। द्रमुक की लगाम एम. करुणानिधि से एम. के. स्टालिन और अब उदयनिधि स्टालिन के पास चली गई। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के इर्द-गिर्द ही घूमती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सोरेन परिवार का नियंत्रण बना हुआ है। ये बहुलवादी नेतृत्व के नहीं, बल्कि विरासत में मिले नेतृत्व के उदाहरण हैं। परिवार को हटा दिया जाये, तो पार्टी ढह ही जाये।

इस बात को समझने के लिए कि भाजपा अलग तरह से क्यों काम करती है, हमें इसके संस्थागत ढांचे पर गौर करना होगा। भाजपा का संगठन स्तरीकृत, सामूहिक और लक्ष्य-उन्मुख है। वहां कार्यकर्ताओं को बहुत जल्दी ही पहचान लिया जाता है और उन्हें व्यवस्थित कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है और बूथ, मंडल, जिला और राज्य स्तर पर जिम्मेदारी देकर परखा जाता है। प्रत्येक चरण में किया गया प्रदर्शन अगले अवसर का निर्धारण करता है। चुनाव जीते जाने वाली प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन ये संगठन की लामबंदी, लोगों को समझाने और परिणाम देने की क्षमता का भी लेखा-जोखा होती हैं। यह संरचना एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करती है जिसमें सेवा, अनुशासन और परिणाम ही आगे बढ़ने के पैमाने हैं।

हरदीप सिंह पुरी
(केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री)

नेतृत्व की पाइपलाइन की भी यही कहानी है। वर्ष 2014 से पार्टी ने पहली पीढ़ी के वैसे नेताओं को आगे बढ़ाया है जो भारत की सामाजिक गतिशीलता को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं ने निरंतर जमीनी स्तर पर काम करके अपना करियर बनाया। ओडिशा में मोहन माझी ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिलने से पहले संगठन और विधानमंडल में वर्षों बिताए। हरियाणा में नायब सिंह सैनी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और राजस्थान में भजन लाल शर्मा वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र में काम करके और पार्टी की जिम्मेदारी निभाकर आगे बढ़े। इनमें से किसी को भी राजनीतिक पद विरासत में नहीं मिला। इनमें से प्रत्येक इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि एक योग्यता-आधारित पार्टी में नेतृत्व कैसे अर्जित किया जा सकता है।

भाजपा का संसदीय और सरकार में रहने का अनुभव भी पहुंच और प्रभुत्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। कई युवा नेताओं को दृश्यता और जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनका मूल्यांकन उनके काम के आधार पर किया जाता है। मंत्रियों का मूल्यांकन परिणामों, सुधारों और जन संवाद के आधार पर किया जाता है। पार्टी के पद समयबद्ध और प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। इससे त्रुटि या महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं होती और न ही कोई भी संस्था ऐसा कर सकती है। लेकिन यह कवायद ऐसे प्रोत्साहन पैदा करती है, जो वंशावली की तुलना में योग्यता को प्राथमिकता देते हैं।

इसके उलट, वंशानुगत पार्टियां नए प्रयोगों को आजमाने में जूझती हैं क्योंकि वहां उत्तराधिकार पूर्वनिर्धारित होता है। वहां प्रतिभाएं अपने उत्तराधिकारी की रक्षा करने की जरूरत के बोझ से घिरी रहती हैं। पारिवारिक परंपरा के विरोधाभास के डर से आंतरिक बहस मंद पड़ जाती है। संगठनात्मक नेटवर्क प्रशासकों और विधायकों के बजाय दरबारियों और दलालों के इर्द-गिर्द घूमने लगते हैं। इसका नतीजा न केवल राजनीतिक गतिरोध में होता है, बल्कि जनता के विश्वास का भी क्षरण होता है। मतदाता अंततः अर्जित नेतृत्व और हस्तांतरित नेतृत्व के बीच के अंतर को पहचान लेते हैं। इतिहास को स्वीकार करना जरूरी होता है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय कल्पना में राजनीतिक विरासत को आम बात बना दिया। वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस से लेकर तृणमूल तक, कई क्षेत्रीय वंशवादी संगठन कांग्रेस की ही शाखाएं हैं और उन्होंने उसके वंशानुगत ढांचे की नकल की है। दशकों से इस संस्कृति ने राजनीतिक दलों को ऐसे पारिवारिक उद्यमों में बदल दिया है, जहां विचारधारा की जगह निष्ठा ने ले ली और नेतृत्व के विकास की जगह उत्तराधिकार के नियोजन ने ले ली। यह मॉडल कुछ समय तक चुनावी सफलता तो दिला सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी टिकाऊ संस्थाओं या सक्षम नेताओं की एक व्यापक श्रृंखला का निर्माण कर पाता है।

आलोचक कभी-कभी यह पूछते हैं कि क्या भाजपा पूरी तरह से वंशवादी हस्तियों से मुक्त है। इसका ईमानदार जवाब यह है कि ऐसा नहीं है और न ही कोई भी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी हो सकती है। लेकिन प्रासंगिक सवाल कुछ दूसरा है। क्या ऐसे व्यक्ति केवल अपने वंश की बदौलत ही पदों पर आसीन होते हैं या उन्होंने फिर निरंतर कार्य करके संगठन और मतदाताओं का विश्वास अर्जित किया है। भाजपा का रिकॉर्ड दर्शाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जीवनी संबंधी तथ्य हो सकती है, लेकिन यह योग्यता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। नेतृत्व का रास्ता सभी के लिए एक जैसा ही है - कार्यकर्ता से नेता, कार्यकर्ता से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि से मंत्री और हर कदम प्रदर्शन के जरिए ही अर्जित किया जाता है।

यह अंतर अपने सामाजिक और भौगोलिक आधार का विस्तार करने की भाजपा की क्षमता को भी दर्शाता है। एक योग्यता-आधारित पार्टी नए समुदायों और क्षेत्रों का समावेश कर सकती है क्योंकि वह भागीदारी के ऐसे रास्ते प्रदान करती है, जो किसी परिवार से निकटता पर निर्भर नहीं होते। वह स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान कर सकती है, उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है और उनके परिणामों को पुरस्कृत कर सकती है। इस तरह ही एक पार्टी स्थानीय वास्तविकताओं में निहित रहते हुए राष्ट्रीय चरित्र हासिल करती है। इसी तरह ही एक पार्टी ऐसे नेताओं के जरिए विचारधारा को शासन में परिवर्तित करती है, जिन्हें केवल विरासत में पाने के बजाय कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है।

मतदाता इस अंतर को पहचान चुके हैं। मतदाता नाम से प्रभावित नहीं होते। वे नेताओं का मूल्यांकन उनके वंश से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से करते हैं। वे जनसेवा से अर्जित वैधता और वंश-परंपरा से प्राप्त अधिकार के बीच का अंतर समझते हैं। इसीलिए, वंशवादी राजनीति से संबंधित बहस को केवल आंकड़ों के खेल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। गंभीर मुद्दा नेतृत्व की संस्कृति का है। क्या कोई पार्टी सेवा और योग्यता को पुरस्कृत करती है या फिर किसी परिवार से जुड़ाव को। इस कसौटी पर भाजपा की खूबी बिल्कुल साफ नजर आती है।

इंडियन एक्सप्रेस के लेख में यह पूछा गया कि भारत की कौन सी पार्टियां परिवारों द्वारा संचालित हैं। लेकिन इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनमें से कौन सी पार्टी परिवार द्वारा संचालित नहीं हैं। भाजपा उन चंद पार्टियों में से एक है जहां नेतृत्व विरासत में नहीं मिलता, केवल अर्जित किया जाता है। पार्टी में विभिन्न पृष्ठभूमि के नेता आते रहेंगे, जिनमें वे भी शामिल होंगे जिनके रिश्तेदार सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन उन्नति की शर्तें सभी के लिए एक जैसी ही होंगी। कड़ी मेहनत कीजिए, विश्वास अर्जित कीजिए, परिणाम दीजिए और लोगों को आश्वस्त कीजिए। लोकतंत्र में इसके अलावा और कोई स्थायी रास्ता नहीं है।

भारत का लोकतंत्र एक मौन बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नागरिक वंशावली के बजाय योग्यता से शासित होने के अपने अधिकार पर जोर दे रहे हैं। जैसे-जैसे नेतृत्व अधिक जवाबदेह होता जा रहा है, संस्थाओं में आत्मविश्वास लौट रहा है। राजनीति विरासत से कम और सेवाभाव से अधिक प्रभावित दिखने लगी है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं। हर पीढ़ी को इसे नवीनीकृत करते रहना होगा। लेकिन दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। योग्यता मायने रखती है। प्रदर्शन मायने रखता है। जनता सबसे अधिक मायने रखती है।

इस मायने में, भाजपा एक अनूठी पार्टी है। इसलिए नहीं कि वह पूर्णता का दावा करती है, बल्कि इसलिए कि उसने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो नेतृत्व अर्जित करने पर जोर देती है। भारत के सार्वजनिक जीवन में यही वह खूबी है जिसे बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह सत्ता को जवाबदेही से और महत्वाकांक्षा को सेवा से जोड़ती है।

झींगा से लेकर सॉफ्टवेयर तक - नए व्यापार समझौते से भारत के लिए बड़ा बाजार खुला

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत ने समृद्धि का एक और दरवाजा खोल दिया है। उसने प्रति व्यक्ति 100,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक आय वाले यूरोपीय देशों के एक धनी समूह के साथ एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे भारतीय किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक आकर्षक बाजार में पहुंचने का रास्ता खुल गया है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को पर्याप्त गति मिलेगी।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) - स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन - के साथ हुआ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) ऐतिहासिक है। यह समझौता 1 अक्टूबर को शुभ नवरात्रि के दौरान लागू हुआ। ईएफटीए के सदस्य देशों ने 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का संकल्प लिया है - जो दुनिया में किसी भी व्यापार समझौते में जतायी गई पहली ऐसी प्रतिबद्धता है। इस समझौते के जरिए, ईएफटीए के सदस्य देशों की सरकारें भारत में निवेश को बढ़ावा देंगी, कम से कम दस लाख रोजगार सृजित करेंगी और प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' मिशन को गति प्रदान करेंगी।

विकसित भारत हेतु व्यापार की रणनीति: मोदी सरकार ने अतीत की झिझक को छोड़कर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अपनाया है। ये समझौते हमारे उत्पादों और सेवाओं को प्रीमियम एवं विकसित बाजारों में पहुंचाते हैं। ये समझौते न सिर्फ नए दरवाजे खोलते हैं, बल्कि हमारे उद्योगों को सशक्त बनाते तथा हमें आगे बढ़ने में मदद करने वाले प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता का संचार भी करते हैं। भारत ने जहां जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, वहीं यूरोपीय संघ के साथ बातचीत भी अच्छी तरह आगे बढ़ी है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दोनों पक्षों के लिए लाभदायक समझौते हुए।

प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी छाप छोड़ने के आत्मविश्वास से भरा हुआ, भारतीय उद्योग जगत आज बुलंदियों पर खड़ा है। यूपीए शासन के दौरान किए गए जल्दबाजी भरे सौदों के उलट, गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए मोदी-युग के हर मुक्त व्यापार समझौते का उद्योग जगत के विभिन्न

पीयूष गोयल
(लेखक भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)

हितधारकों ने खुले दिल से स्वागत किया है। यूपीए शासन के सौदे बिना किसी जानकारी के और अक्सर उन प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किए गए थे, जिन्हें हमारे बाजारों तक पहुंच तो मिली, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे पर्याप्त रूप से नहीं खोले। भारत को आकर्षक बनाना - यह बदलाव 11 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को "नाजुक पांच" के तमगे से उबारकर इसे व्यापार एवं पूंजी के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बनाया। मोदी सरकार ने बुनियादी सुधारों के जरिए विरासत में मिली समस्याओं, गतिरोध, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को दूर किया। अकेले उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने मार्च 2025 तक कुल 1.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ने लागत में कमी की है और बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित किया है। हमारी डिजिटल रीढ़ - जन-धन, यूपीआई और ट्रेड कनेक्ट - ने अवसरों का लोकतंत्रीकरण किया है और छह वर्षों में कुल 12,000 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 65,000 करोड़ लेनदेन को संभव बनाया है। इससे वंचित वर्ग अब वित्तीय मुख्यधारा में आ गया है।

निवेश और रोजगार सृजन - अब, ईएफटीए के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से दस लाख प्रत्यक्ष और अनगिनत अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का वादा किया गया है। यह निवेश पिछले 25 वर्षों में इन देशों से प्राप्त मात्र 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से कहीं अधिक बड़ा है। वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ, जोकि 14 प्रतिशत की वृद्धि है, वास्तविक प्रवाह जतायी गई प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ सकता है। इसका श्रेय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों और मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानूनों को जाता है, जिनका प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है। टीईपीए प्रवर्तन एवं सुव्यवस्थित सुरक्षा उपायों के मामले में बेहतर सहयोग के जरिए आईपीआर को मजबूत करता है, नवोन्मेषकों को सशक्त बनाता है और ठोस नियामक संबंधी निश्चितता के बीच उच्च-तकनीक से संबंधित पूंजी को आकर्षित करता है। किसान और मछुआरे - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अलावा, वस्त्र तथा रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र से जुड़े निर्यात में भी तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ईएफटीए के समृद्ध उपभोक्ता हमारे कृषि उत्पादों, चाय और कॉफी के लिए लालायित रहते हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी।

आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा।

यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :-

- देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता;
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों;
- गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत;
- राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं; और
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।

पृष्ठभूमि :

केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 01.01.2026 से लागू करना अपेक्षित है।

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके।

जीएसटी सुधार और भारतीय पर्यटन का नया सवेरा

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत ने समृद्धि का एक और दरवाजा खोल दिया है। उसने प्रति व्यक्ति 100,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक आय वाले यूरोपीय देशों के एक धनी समूह के साथ एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे भारतीय किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक आकर्षक बाजार में पहुंचने का रास्ता खुल गया है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को पर्याप्त गति मिलेगी।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) - स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन - के साथ हुआ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) ऐतिहासिक है। यह समझौता 1 अक्टूबर को शुभ नवरात्रि के दौरान लागू हुआ। ईएफटीए के सदस्य देशों ने 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का संकल्प लिया है - जो दुनिया में किसी भी व्यापार समझौते में जतायी गई पहली ऐसी प्रतिबद्धता है। इस समझौते के जरिए, ईएफटीए के सदस्य देशों की सरकारें भारत में निवेश को बढ़ावा देंगी, कम से कम दस लाख रोजगार सृजित करेंगी और प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' मिशन को गति प्रदान करेंगी।

विकसित भारत हेतु व्यापार की रणनीति: मोदी सरकार ने अतीत की झिझक को छोड़कर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अपनाया है। ये समझौते हमारे उत्पादों और सेवाओं को प्रीमियम एवं विकसित बाजारों में पहुंचाते हैं। ये समझौते न सिर्फ नए दरवाजे खोलते हैं, बल्कि हमारे उद्योगों को सशक्त बनाते तथा हमें आगे बढ़ने में मदद करने वाले प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता का संचार भी करते हैं। भारत ने जहां जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक

गजेंद्र सिंह शेखावत
(केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री)

ऐतिहासिक समझौता किया, वहीं यूरोपीय संघ के साथ बातचीत भी अच्छी तरह आगे बढ़ी है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दोनों पक्षों के लिए लाभदायक समझौते हुए।

प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी छाप छोड़ने के आत्मविश्वास से भरा हुआ, भारतीय उद्योग जगत आज बुलंदियों पर खड़ा है। यूपीए शासन के दौरान किए गए जल्दबाजी भरे सौदों के उलट, गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए मोदी-युग के हर मुक्त व्यापार समझौते का उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों ने खुले दिल से स्वागत किया है। यूपीए शासन के सौदे बिना किसी जानकारी के और अक्सर उन प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किए गए थे, जिन्हें हमारे बाजारों तक पहुंच तो मिली, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे पर्याप्त रूप से नहीं खोले। भारत को आकर्षक बनाना - यह बदलाव 11 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को "नाजुक पांच" के तमगे से उबारकर इसे व्यापार एवं पूंजी के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बनाया। मोदी सरकार ने बुनियादी सुधारों के जरिए विरासत में मिली समस्याओं, गतिरोध, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को दूर किया। अकेले उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने मार्च 2025 तक कुल 1.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ने लागत में कमी की है और बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित किया है। हमारी डिजिटल रीढ़ - जन-धन, यूपीआई और ट्रेड कनेक्ट - ने अवसरों का लोकतंत्रीकरण किया है और छह वर्षों में कुल 12,000 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 65,000 करोड़ लेनदेन को संभव बनाया है।

भारत की श्रम संहिताएं : समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भूमि और श्रम; भारत के विकास के आधार-स्तंभ हैं– भूमि अवसंरचना और औद्योगिक विकास को गति देती है, जबकि श्रम उत्पादकता और समावेश को बढ़ावा देता है। इस संदर्भ में, भारत की नई श्रम संहिताएं एक परिवर्तनकारी कदम को रेखांकित करती हैं, 29 कानूनों को एक आधुनिक, एकीकृत संरचना में समेकित करती हैं तथा श्रम परिदृश्य में स्पष्टता, एकरूपता और समानता सुनिश्चित करती है। श्रमिकों के लिए, ये संहिताएं मज़बूत सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और औपचारिक लाभों तक व्यापक पहुँच की सुविधा प्रदान करती हैं, जबकि व्यवसायों को सरलीकृत अनुपालन, कार्यबल प्रबंधन में लचीलेपन और सभी क्षेत्रों में समान अवसर का लाभ मिलता है। हालाँकि अंतिम प्रभाव कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, लेकिन ये संहिताएँ भारत के श्रम बाजार को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं।

जयपुर में वितरण सेवाओं से लेकर साणंद में तकनीकी भूमिकाओं और गुवाहाटी में निर्माण कार्य तक– विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल की आकांक्षा एक-जैसी है: सुरक्षित कार्य परिस्थितियों तक पहुँच, उचित पारिश्रमिक और दूसरी जगह ले जाने योग्य एवं विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा। श्रमिक चाहे कारखानों में कार्यरत हों या खेतों में, या प्लेटफ़ॉर्म-आधारित सेवाओं से जुड़े हों, वे तीन प्रमुख आश्वासन चाहते हैं: आय स्थिरता, पूर्वानुमानित सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार में सम्मान। भारत की चार श्रम संहिताएँ इस आकांक्षा को जीवंत वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से तैयार

चंद्रजीत बनर्जी
(महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई))

की गई हैं, ताकि समता और सुरक्षा के सिद्धांत का कार्य जगत में अंतर्निहित होना सुनिश्चित हो सके।

सुधारों के केंद्र में है - सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार। लाखों असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक, जो भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, नई व्यवस्था के तहत औपचारिक मान्यता प्राप्त करेंगे और कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे। भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ के प्रावधान अब औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों तक इनका विस्तार हो जाएगा। यह बदलाव, न केवल कमजोर श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुविधा को मजबूत करता है, बल्कि उद्यमों को रोज़गार को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा के समग्र आधार का विस्तार होता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 औपचारिक रूप से गिग, प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित श्रमिकों को मान्यता देती है तथा केंद्र और राज्यों को उनके लिए समर्पित सामाजिक-सुरक्षा कोष स्थापित करने की सुविधा देती है। एग्रीगेटर्स को टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत, भुगतान का अधिकतम 5 प्रतिशत, योगदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लाभों के वित्तपोषण का एक व्यावहारिक तरीका है। आधार-आधारित पंजीकरण पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और ई-श्रम पोर्टल में 31 करोड़ से अधिक श्रमिक नामांकित हैं। प्रत्येक श्रमिक को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन) दी गयी है, जिसके जरिये स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व सहायता, या वृद्धावस्था पेंशन जैसे लाभों को नये कार्य-स्थल में स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी काम करते हों। ई-श्रम रजिस्ट्री, वास्तव में, अनौपचारिक श्रमिकों के संदर्भ में भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है– जो समावेशी विकास और आपदा सहनीयता की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

सर्वजीत कौर मानुके ने अधिकारियों से की प्रत्येक योग्य नागरिक तक लाभ पहुंचाने की अपील

• जालंधर ब्रीज. जालंधर

पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने आज जालंधर में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। समिति की अध्यक्ष और जगराओं से विधायक सर्वजीत कौर मानुके की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विधायक अमित रतन और डा. नछत्तरपाल के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क, ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) नवदीप कौर और प्रमुख विभागों के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने जालंधर में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की

अध्यक्ष सर्वजीत कौर मानुके ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कैम्प के माध्यम से अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रहे। समिति ने पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ-साथ पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की अपडेट भी मांगी। बैठक के दौरान, समिति ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इसके अलावा, अधिकारियों को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण में लगे कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क खाद्य वितरण, जननी सुरक्षा योजना, वर्दी व पुस्तकों के वितरण के साथ-साथ शौचालय निर्माण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने जाति सर्टिफिकेट जारी करने में तेजी लाने और आवेदकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश अवधि के दौरान एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की भी सिफारिश की।

अली मुहल्ले में अवैध निर्माण ध्वस्त, आरोपी के खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज

'युद्ध नशे के विरुद्ध' के तहत सिविल और पुलिस अधिकारियों द्वारा कुख्यात नशा तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई

• जालंधर ब्रीज. जालंधर

पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम 'युद्ध नशे के विरुद्ध' के तहत जालंधर में सख्त कार्रवाई को अमल में लाते हुए जालंधर नगर निगम ने जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से आज अली मुहल्ला इलाके में कुख्यात नशा तस्कर से संबंधित एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जालंधर नगर निगम और जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के तहत अमरजीत सिंह पुत्र बनारसी दास निवासी अली मुहल्ला थाना डिवीजन नंबर 4 जालंधर की अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अमरजीत सिंह कुख्यात नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 10 मुकदमे एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज है।

उन्होंने कहा कि नशे से जुड़ी कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी कार्रवाइयां आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नागरिकों से नशों से संबंधित कोई भी जानकारी सरकार द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9779-100-200 पर साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को निमंत्रण

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़/गांधीनगर

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्यभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

अमन अरोड़ा ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जा रहे महीनेभर चलने वाले राज्यव्यापी यादगारी कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी की शहादत सिख इतिहास में भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का नींव-पत्थर है और यह सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का विश्वव्यापी सिद्धांत है।

इस अवसर पर तरुनप्रीत सिंह सौंद ने इन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विश्वभर के लोगों को गुरु साहिब जी की अनुपम शहादत के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे।

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलाव की साक्षी बन रही है : चीमा

वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के 7 संगठनों के साथ की बैठकें, जायज़ मांगों के समाधान का दिया भरोसा

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के 'शिक्षा क्रांति' कार्यक्रम के तहत किए जा रहे बुनियादी ढांचे के व्यापक उन्नयन, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों एवं मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव की साक्षी बन रही है। वित्त मंत्री चीमा ने यह टिप्पणियाँ आज यहां शिक्षा विभाग की 7 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान कीं। इन संगठनों में स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, बेरोजगार बी.एड.-टेट पास अध्यापक यूनियन, ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (सुनील फाज़िलका) और ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) शामिल थे। वित्त मंत्री ने

उनकी मांगों की व्यापक समीक्षा की और यूनियन के सदस्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए अधिक समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने वित्त मंत्री को बताया कि यूनियनों की अधिकांश मांगों का समाधान या तो अंतिम चरण में है या उन पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अन्य जायज़ मांगों को भी शीघ्र ही हल कर दिया जाएगा।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह जायज़ मांगों से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों को वित्त विभाग के साथ साझा करे ताकि बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके। एक अलग बैठक में, वित्त मंत्री चीमा ने ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के साथ भी सार्थक चर्चा की और उनके मुद्दों को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से हल करने का भरोसा दिया। इन बैठकों के दौरान विशेष सचिव (परसोनल) उपकार सिंह और विशेष सचिव (वित्त) अजय अरोड़ा ने वित्त मंत्री को यूनियनों द्वारा रखी गई मांगों के संबंध में अपने-अपने विभागों की स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट से वीरपाल कौर सिधाणा, मनप्रीत सिंह मोगा, परमजीत कौर पक्खोवाल; कंप्यूटर अध्यापक यूनियन से गुरविंदर सिंह, राखी मनन, हरप्रीत सिंह; कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी से जॉनी सिंगला, नरदीप शर्मा, सुनीत सरीन; बेरोजगार बी.एड.-टेट पास अध्यापक यूनियन से जसवंत घुबाया, हरदीप सिंह, संदीप सिंह; ई.टी.टी. टेट पास अध्यापक यूनियन (सुनील फाज़िलका) से सुनील कुमार, सलविंदर सिंह, रणजीत सिंह; ई.टी.टी. टेट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) से कमल ठाकुर, सोहन सिंह और गुरमुख सिंह तथा ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन से संदीप सिंह, किरणदीप सिंह और प्रदीप सिंह ने अपने मुद्दे उठाए।

विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज की सृजन के लिए आगे आने का न्योता

विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के तहत आयोजित सैमिनार

• जालंधर ब्रीज. जालंधर

प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार के निर्देशानुसार विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब द्वारा 'चौकसी : हमारी साझी जिम्मेदारी' थीम के तहत विजिलेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट जालंधर द्वारा आज सत्यम इंस्टीट्यूट, गांव जीवन नंगल (नकोदर) में सैमिनार आयोजित किया गया।

सैमिनार के दौरान विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज की सृजन के लिए आगे आने का न्योता दिया गया। उप कप्तान पुलिस, विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट जालंधर अश्वनी कुमार और इंस्पेक्टर साहिल अग्निहोत्री ने उपस्थित लोगों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो को सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत मांगता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या सरकारी कार्य में घपलेबाजी करता है, तो इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-1800-1000 और वेबसाइट www.vigilancebureau.punjab.gov.in एंटी करप्शन एक्शन लाइन व्हाट्सएप नंबर 95012-00200 पर शिकायत की जा सकती है। इस दौरान उपस्थित लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई और पैंफलेट वितरित किए गए।

सैमिनार में सत्यम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन विपन कुमार शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम शर्मा, चेयरपर्सन ज्योति शर्मा, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रशीद हामिद, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल पारस चड्ढा, सत्यम स्कूल के प्रिंसिपल पंकज शर्मा, स्टाफ मेंबर और कॉलेज के बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

डिजिटल स्वास्थ्य और बायोमेडिकल डेटा विज्ञान में एमओयू पर हस्ताक्षर

• जालंधर ब्रीज. रोपड़/चंडीगढ़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (आईआईटी रोपड़) और ICMR-राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरडीएचएस) ने डिजिटल स्वास्थ्य, बायोमेडिकल डेटा एनालिटिक्स और स्वास्थ्य देखभाल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू प्रो. राजीव आहूजा, निदेशक, आईआईटी रोपड़ और डॉ. मोना दुग्गल, निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरडीएचएस द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। यह रणनीतिक साझेदारी दो प्रमुख संस्थानों के बीच दीर्घकालिक सहयोग की शुरुआत को दर्शाती है, जो बहु-विषयक अनुसंधान, अकादमिक आदान-प्रदान और ट्रांसलेशनल नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस एमओयू के तहत, आईआईटी रोपड़ और आईसीएमआर-एनआईआरडीएचएस संयुक्त रूप से डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी तथा मास्टर कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन करेंगे। दोनों संस्थान स्वास्थ्य तकनीक के उभरते क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करेंगे और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों को संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी विकास पहलों के माध्यम से ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगे।

यह सहयोग डेटा-आधारित और तकनीक-सक्षम समाधानों के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों की नई पीढ़ी को तैयार करने का प्रयास करता है।

ईटीओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत कार्यों की समीक्षा

लोक निर्माण मंत्री द्वारा मरम्मत कार्यों के आवंटन में और तेजी लाने के निर्देश

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत (स्पेशल रिपेयर) कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य द्वारा सड़कों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 10,778 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है।

बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही वर्तमान विशेष मरम्मत का संबंध वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में विशेष मरम्मत हेतु ड्यू हुई सड़कों से संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली 81 मार्केट कमेटियों की सड़कों पर काम किया जाएगा। इन सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कार्यों का आवंटन किया गया है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने मरम्मत कार्यों के आवंटन में और तेजी लाने तथा इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बताया कि डिपार्टमेंट विजिलेंस कमेटी की ओर से नाभा मार्केट कमेटी की लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क की जांच की गई और उन्होंने निर्माण कार्य में पाई गई कमियों को मौके पर ही सुधारने की सराहना की और भविष्य में भी ऐसी जांचें जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विकास प्रताप, विशेष सचिव हरगुंजीत कौर, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य इंजीनियर श्री विजय चोपड़ा, अनिल गुप्ता, रमतेश बैंस, अर्शदीप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सेवा केंद्रों में मिलेंगी आरटीओ कार्यालय से संबंधित 56 सेवाएं : अमनदीप कौर

होशियारपुर (जालंधर ब्रीज). रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी अमनदीप कौर घुम्मण ने बताया कि पंजाब सरकार ने जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि विभाग से संबंधित 56 सेवाओं को अब सेवा केंद्रों में शुरू कर दिया गया है।

आर.टी.ओ होशियारपुर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुल 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं जिले में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए खुद ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ सेवा केंद्र के माध्यम से भी सेवाएं ले सकते हैं।

अमनदीप कौर घुम्मण ने बताया कि अब जिला वासियों को आर.टी.ओ. दफ्तर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेवाएं जिले में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इसके लिए इन केंद्रों के स्टाफ को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उनकी सहायता के लिए आर.टी.ओ कार्यालय में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने अभिषेक नायर को बनाया मुख्य कोच

स्पोर्ट्स डेस्क. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल के 2026 संस्करण से पहले अभिषेक नायर को फ्रैंचाइज़ी का मुख्य कोच नियुक्त किया है। 2018 से फ्रैंचाइज़ी से जुड़े नायर को पहली बार मुख्य कोच की भूमिका में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने अनुभवी घरेलू कोच चंद्रकांत पंडित की जगह ली है, जो तीन सीज़न तक फ्रैंचाइज़ी के प्रमुख रहे थे। मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले भारतीय सहयोगी स्टाफ से निकाले जाने के बाद, नायर आईपीएल के 2025 संस्करण के बीच में फ्रैंचाइज़ी में लौट आए।

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक फ्रैंचाइज़ी बयान में कहा, "अभिषेक 2018 से नाइट राइडर्स टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर हमारे खिलाड़ियों को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। खेल के प्रति उनकी समझ और खिलाड़ियों के

जुड़ाव हमारे विकास में महत्वपूर्ण रहा है। हम उन्हें मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालते हुए और केकेआर को उसके अगले अध्याय में ले जाते हुए देखकर रोमांचित हैं।" नायर, जिन्हें दिनेश कार्तिक और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों ने सफेद गेंद के खेल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए खुले तौर पर स्वीकार किया है, को डब्ल्यूपीएल टीम यूपी वॉरियर्स ने भी मुख्य कोच नियुक्त किया था। नायर 2018 में केकेआर अकादमी में मुख्य कोच के रूप में शामिल हुए और जल्द ही टीम के सहयोगी स्टाफ में शामिल हो गए। नायर उस समय टीम से जुड़े थे जब जैक्स कैलिस मुख्य कोच थे, जिनकी जगह बाद में ब्रेंडन मैकुलम और पंडित ने ले ली।

नायर 2024 में पंडित और गंभीर के साथ सहायक कोच के रूप में फ्रैंचाइज़ी के साथ थे, जो केकेआर द्वारा अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीतने के समय मेंटर थे, और श्रेयस अय्यर कप्तान थे। नायर ने 2022 में सीपीएल में नाइट राइडर्स की सैटेलाइट फ्रैंचाइज़ी, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया।

साइंस सिटी में मानक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विशेषज्ञ की बैठक

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). मानक शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पुष्पा गुप्ता साइंस सिटी द्वारा पंजाब भर के शैक्षिक संस्थानों के निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानाचार्यों की एक बैठक की मेजबानी की गई। इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्कूलों और साइंस सिटी के बीच एक संबंध मजबूत करना था ताकि विज्ञान की शिक्षा अधिक पहुंच योग्य बने।

ऐसे प्रयासों के माध्यम से छात्र को वर्ग में अनौपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ने के लक्ष्य प्रभावी तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए पुष्पा गुजराल साइंस सिटी की डायरेक्टर डॉ. राजेश गरोवर ने शिक्षा के भविष्य की बेहतरी के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करते हुए इस बात पर बल दिया कि ऐसी अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है जो विज्ञानिक सोच, नवीनता और रचनात्मकता को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करे।

इस अवसर पर मेहमानों को साइंस सिटी का विस्तृत दौरा करवाया गया। इस अवसर पर पंजाब के विभिन्न जिलों से शिक्षाविदों को साइंस सिटी का ईको-ईको शख्स भी दिखाया गया, जहां जिला शिक्षाधिकारी और स्कूल प्रमुखों ने धरती के विभिन्न प्रकार के वातावरण का अनुभव प्राप्त किया।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.